



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 1990/फाल्गुन 23, 1911

No. 61] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 1990/PHALGUNA 23, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 15/ई.टी.सी. (पी.एन.)/90

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1990

विषय — 1 जनवरी, 1988 से 31 दिसम्बर, 1990 तक खुले
सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत संयुक्त राज्यां अमेरिका,
यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों, आस्ट्रिया,
फ़िनलैंड, स्वीडन, नावे और कनाडा को गारमेट्स और
निटवियर के निर्यात हेतु स्कीम।

क्र.सं. 2/19/88 ई. 1.—उपर्युक्त विषयक 15 अक्टूबर, 1987
की सार्वजनिक सूचना सं. 28-ई.टी.सी. (पी.एन.)/87 और बाद के
संशोधनों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह निर्णय किया
गया है कि सार्वजनिक सूचना को आगे निम्न प्रकार से संशोधित किया
जाएगा:—

2. पैरा 6 के उपपैरा (5)(क) को हटा दिया जाए।

3. पैरा 6 के उपपैरा 5(ख) को निम्नोक्त द्वारा प्रतिस्थापित
किया जाएगा:—

6(5)(ख) अन्तर्गत की अन्तर्गत मात्रा के निर्यात हेतु सम्बद्ध
अवधि जिसमें अन्तरण प्रभावी हुआ है की समाप्ति
से 30 दिनों का समय अनुमति होगा। 30 दिसम्बर
के उपरान्त 31 दिसम्बर तक पोतलदान के लिए
दूसरी अवधि के लिए अन्तरित हकदारियों की
अनुमति माह-पत्र द्वारा अनुसमयित विशेष सविदाओं के
मद्दे जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 20% की
दर में जमा, पेसगी राशि/बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने के
अध्यक्षीय दो जाएगी।”

4. पैरा 8(3) को निम्नोक्त द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“8(3) इस सिस्टम के अन्तर्गत आवंटन सम्बन्धित आवंटन अवधि
के अन्त तक बंध होगा अर्थात् आवंटन। अप्रैल से आगे
किया जाएगा जो कि 30 जून तक बंध होगा। 1 अगस्त
से आगे किए गए दूसरी अवधि के आवंटन 30 अक्टूबर
तक बंध होंगे। 1 अक्टूबर से आगे किए गए आवंटन
31 दिसम्बर तक बंध होंगे।

5. पैरा 11 के उप पैरा (4) में शब्द “25 देश/क्षेत्रों” को “15 देश/क्षेत्रों” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

6. पैरा 16 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

16. निम्नलिखित हकदारों के प्रमाणन की वैध अवधि:—

भूतकालीन निर्यातन हकदारों/नए-कालीन हकदारों/विनिर्माण निर्यातन हकदारों और केन्द्र/राज्य निर्यातन सिस्टम के मामलों में पोतलदान बिलों के संबंध में प्रमाणन 30 दिन का अवधि के लिए बंध होगा।

वर्तमान अवधि का समय पड़ोसों में वैधता का विस्तारार्थ हकदारों को नूतन अवधि का प्रमाणन से अधिकतम 30 दिनों का अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 31 दिसम्बर के पश्चात् नहीं यह इस शर्त के अधीन होगा कि निर्यातन जड़-ज-परिणत निर्यातन मूल्य के 15% का निर्यात अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रस्तुत करना हो। वैधता को पुनः 30 दिनों का अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है लेकिन 31 दिसम्बर के बाद नहीं, वह इस शर्त पर कि निर्यातन जड़-ज-परिणत निर्यातन मूल्य के 15% का निर्यात अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रस्तुत करना हो। दूसरे शब्दों में, वैधता का विस्तारार्थ नूतन अवधि का प्रमाणन से 60 दिनों का अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 31 दिसम्बर के बाद नहीं, वह इस शर्त पर कि निर्यातन जड़-ज-परिणत निर्यातन मूल्य के 25% का निर्यात अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रस्तुत करना हो।

वैधता देने के लिए अग्रेज एफार्सोर्ट प्रावधान काउन्सिल सक्षम होगी। ऊपर दिए गए के अतिरिक्त, शर्तों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। प्रावधान आदेश यदि कड़ा लागू हो जाए तो केवल ईएमडी/बोर्डों को अवधि के प्रमाणन के लिए विचारणीय होंगे निर्यात हकदारों के प्रमाणन का वैधता अवधि के विचार के प्रमाणन के लिए नहीं।

7. गारंटी पर यथावत 15 अक्टूबर, 1987 को सार्वजनिक सूचना सं. 28-ई.टी.सी. (प.प.)/87 द्वारा अधिसूचित स्काम के समान अवधि अवधि नहीं रहेगी।

तेजेंद्र खन्ना,
मुख्य निर्यात, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(EXPORT TRADE CONTROL)

PUBLIC NOTICE NO. 15-ETC (PN)/90

New Delhi, the 14th March, 1990

Subject :—Scheme for export order GCL 3 of garments and knitwear to USA, EEC Member States Austria, Finland, Sweden, Norway and Canada from 1st January, 1988 to 31st December, 1990.

File No. 2/19/88-E-I.—Attention is invited to Public Notice No. 28-ETC (PN)/87, dated the 15th October, 1987 and subsequent amendments on the above subject. It has been decided to further amend the Public Notice as following :—

2. Sub-para (v) (a) of para 6 is deleted.

3. Sub-para (v) (b) of para 6 is substituted by the following :—

“6(v)(b) A transferee would be allowed 30 days from the end of the relevant period, in which transfer is effected, to export the transferred quantity. Transferred entitlements of the 2nd period would be permitted for shipment beyond 30th September upto 31st December against specific contracts backed by Letter of Credit subject to submission of Earnest Money Deposit/Bank Guarantee at the rate of 20 per cent of FOB value.”

4. Para 8(iii) is substituted by the following :—

“8(iii) Allotments under this System will be valid upto the end of the relevant allotment period, i. e. allotments to be made from 1st April, onwards will be valid upto 30th June. The second period allotments made from 1st August onwards will be valid upto 30th October. Allotments to be made from 1st October onwards will be valid upto 31st December.”

5. In sub para (iv) of para 11 the words “25 countries/categories” are substituted by the words “15 countries/categories.”

6. Para 16 is substituted by the following :—

“16. Validity Period of Certification of Export Entitlement :—

A certification on the shipping bills shall be valid for a period of 30 days in the case of Post Performance, Entitlement/Non-quota Entitlement/Manufacturer Exporters Entitlement and Central/State Corporations Systems.

Provided that in all systems of allotment validity can be extended for a maximum period of 30 days from the original expiry of the entitlement in question, but not beyond 31st December, subject to the exporter submitting a net additional Bank Guarantee of 15 per cent of FOB value. Validity can be further extended by another 30 days, but not beyond 31st December subject to the exporter submitting a net additional bank guarantee of 10 per cent of FOB value. In other words, in all systems of allotment, validity can be extended for a maximum period of 60 days from the original expiry of the entitlement in question, but not beyond 31st December, subject to the exporters submitting a net additional Bank Guarantee of 25 per cent of FOB value. The Apperal Export Promotion Council shall be competent to grant the extensions. There shall be no extension of quotas except as provided above. Force majeure conditions, where they arise, shall be considered for the purpose of forfeiture of ETD Bank Guarantee, and not for the purpose of extension of validity period of Certification of Export Entitlements.”

7. All other provisions of the Scheme notified in Public Notice No. 28-ETC(PN)/87 dated the 15th October, 1987, as amended from time to time, remain unchanged.

TEJENDRA KHANNA, Chief
Controller of Imports & Exports.